RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-07
July-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

आजादी से 2015–16 तक की ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास हेतु प्रयास

[1]सिंह राजेन्द्र कुमार [2]भाटी डॉ. जे0एस0 [3*]चन्द्र डॉ. प्रकाश

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराणा भूपाल नॉबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
[3]व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राज0उ0मा0वि0, गणेशपुर(आसपुर)जिला–डूंगरपुर, राजस्थान

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 July 2019

Keywords
ग्रामीण, विकास, योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी आदि।

***Corresponding Author**
Email: patodia1982[at]gmail.com

ABSTRACT

आजादी से 2015–16 तक की ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास हेतु किये गये प्रयासों का यहां प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन किया गया है। आजादी के बाद ग्रामीण विकास का लक्ष्य उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था जिनको पूरा करना राष्ट्र के विकास हेतु अति आवश्यक था। आजादी के बाद अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं की शुरूआत की गई जिसमें लोगों की आधारभूत सुविधाओं से लेकर उनमें कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना था। जिससे कि ग्रामीण परिवेश सशक्त बन सके, वे एक अच्छे परिवेश में रह सके, अच्छी शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण विकास से जुड़ी अनेक छोटी बड़ी योजनाओं का अध्ययन किया गया, जिनका अध्ययन करना वर्तमान परिपेक्ष्य में अति आवश्यक भी है।

प्रस्तावनाः–

भारतीय ज्वलंत राजनीति में विकास का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, विशेषकर एन0डी0ए0 सरकार (2014–19) में। इस दौरान विकास किस हद तक हुआ इसके कयास विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न लगाये जा रहे हैं। इसके दो पक्ष उभरे हैं एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि विकास हुआ है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है। एन0डी0ए0 सरकार विकास की गति तीव्रता का दोषारोपण पिछली सरकारों पर विशेषकर यू0पी0ए0 सरकार पर लगा रही है।

देश की आजादी के बाद अनेक योजनाओं का क्रियांवयन किया गया। इन योजनाओं को इस लिए चलाया गया कि जल्दी से जल्दी देश आजादी के बाद विश्व के अन्य विकासशील देशों की श्रेणी में आ सके। इन विकास योजनाओं मे महत्वपूर्ण स्थान देश की पंचवर्षीय योजनाओं का रहा है। जबकि वर्तमान में प्रमुख राज्यों में ग्रामीण विकास पर व्यय कम हुआ है[i]।

पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में आजादी के तुरंत बाद पूर्व सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर चलाई गई। ये योजनाएं पांच साल की प्लानिंग थी। इसका श्रेय देश(भारत) के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को विशेषकर जाता है और उन्होंने ही देश के विकास लिए इसकी अत्यावश्यकता महसूस की। इन पंचवर्षीय योजनाओं को 1966 तक बराबर गति मिली लेकिन 1966 में इसकी तारतम्यता टूट गई और तीन एक वर्षीय योजनाओं का संचालन किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1979 तक चलनी थी गैर कॉग्रेसी सरकार बनने के कारण एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई और इस जगह इस योजना का कार्यकाल परिवर्तित किया गया। लेकिन आगे 1980 में वापस कॉग्रेस सत्ता में आने के कारण इस पंचवर्षीय योजना को नये सीरे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार द्वारा शुरू की गई। इसकी तारतम्यता आगे चलकर 1990 को फिर टूट गई क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना दो वर्ष देर से शुरू हुई। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती रही और ये पंचवर्षीय योजनाएं अंततः 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। लेकिन वर्तमान 2014 में बनी नई सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की शुरूआत कर दी गई और योजना आयोग के माध्यम से चलाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया इसके स्थान पर नीति आयोग के माध्यम से चिर कालिन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

साहित्य समीक्षाः–

देवपुरा, प्रतापमल (2012) ने अपनी पुस्तक ''पंचायती राज के नये आयाम'' में लेखक द्वारा पंचायती राज के विभिन्न नवीन आयामों पर विस्तार से चर्चा की गई।

झामड़, लक्ष्मीलाल (2003) शोध अध्ययन "राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता पर निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का प्रभाव– दक्षिणी राजस्थान के सन्दर्भ में" में ग्रामीण गरीबी निवारण सम्बंधित विभिन्न योजनाओं की जाँच की है।

कश्यप, मंजुला (2014) ''ग्रामीण विकास और मनरेगा' लेखक ने मनरेगा के सकारात्मक प्रभावों के अलावा सावधानियां और सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

मेनारिया, सालगराम (2004) ने शोध प्रबंध "ग्रामीण राजस्थान में विकास एवं गतिशीलता के सामाजिक आयाम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में ग्रामीण विकास सम्बंधित शोध कार्य किया है और इस अध्ययन में राजसमन्द जिले की रेलमगरा तहसील के दो गांवों का अध्ययन किया गया है।

आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं और ग्रामीण विकास पर जोरः–

पंचवर्षीय योजनाएं

पंचवर्षीय योजनाएं	अवधि	प्राथमिक क्षेत्र	लक्ष्य
पहली	1951–56	कृषि, बिजली सिंचाई	2.1
दूसरी	1956–61	उद्योग	4.5
तीसरी	1961–66	खाद्य/उद्योग	5.6
चौथी	1969–74	कृषि	5.7
पांचवी	1974–79	गरीबी उन्मूलन	4.4
छठी	1980–85	कृषि/उद्योग	5.2
सातवीं	1985–90	खाद्य/उर्जा	5.0
आठवीं	1992–97	शिक्षा/मानव स्रोत	5.6
नवीं	1997–02	न्याय	6.5
दसवीं	2002–07	रोजगार/उर्जा	8.1
ग्यारहवीं	2007–12	विकास	8.0
बाहरवीं	2012–17	त्वरित	8.0

(स्रोतः– योजना आयोग)

ग्राम और कृषि शब्द एक दूसरे के पूरक है। जहां ग्राम होंगे वहां कृषि कार्य होगा और जहां कृषि कार्य होगा वहां ग्राम होगा। वे पंचवर्षीय योजनाएं जिनमें कृषि विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण पर अत्यधिक जोर दिया गयाः–

- **प्रथम पंचवर्षीय योजनाः–** प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई संबंधित विकास पर जोर दिया गया जिसका सीधा संबंध ग्रामीण विकास से था साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया जो कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजना थी लेकिन यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका।
- **द्वितीय पंचवर्षीय योजनाः–** पी0सी0 महालनोबिस मॉडल[ii] पर आधारित यह योजना कृषि और उद्योग विकास पर आधारित थी। इसमें कृषि पर विशेष ध्यान था क्योंकि कुल खर्च का एक–चौथाई भाग कृषि विकास हेतु खर्च किया जाना था।
- **तीसरी पंचवर्षीय योजनाः–** तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया लेकिन यह योजना सफल नहीं बन पायी क्योंकि इस योजना में भारत को चीन के साथ युद्ध में उलझना पड़ा था। इस योजना का उद्देश्य अक्टूबर 1963 तक कार्यक्रमों का क्रियान्यन करके ग्रामीण क्षेत्रों और निर्धनों की स्थिति में सुधार करना था[iii]। इस योजना में एक बहुत बड़े समुदाय के विकास कार्यक्रमों हेतु एक बहुत बड़ी राशि खर्च करने का लक्ष्य जो कि पहले निर्धारित किया गया था वह प्राप्त नहीं किया जा सका और यह योजना पहली असफल पंचवर्षीय योजना निकली।
- **चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाः–** लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसमें भी ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में बढोत्तरी हेतु एक–चौथाई खर्च का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस योजना के परिणाम भी कुछ ज्यादा सकारात्मक नहीं निकले।
- **पांचवीं पंचवर्षीय योजनाः–** पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जो कि तात्कालिन प्रधानमंत्री थी ने गरीबी हटाओं का नारा दिया। इस योजना का संबंध भी हम ग्रामीण विकास से मान सकते हैं। यह योजना अपनी विपरीत परिस्थियों के बादजूद भी एक सफल योजना सिद्ध हुई।
- **छठी पंचवर्षीय योजनाः–** एक वर्ष के बाद छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया यह योजना ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी।
- **सातवीं पंचवर्षीय योजनाः–** सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं की शुरूआत की गई जिसमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का विलय किया गया। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को मजबूत करने का प्रयास किया गया।
- **आठवीं पंचवर्षीय योजनाः–** यहां दो वर्षीय योजना अवकाश के बाद 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का लक्ष्य था "रोजगार के साथ विकास"। यह एक ऐसी योजना थी जो कि उदारीकरण से संबंधित प्रथम योजना थी। यह योजना भी ग्रामीण विकास में सफल रही।
- **नवीं पंचवर्षीय योजनाः–** इस योजना में भी गरीबी पर काबू पाने का प्रयास किया गया विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास पर इसमें जोर दिया गया। यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पायी।
- **दसवीं पंचवर्षीय योजनाः–** दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर सुलभ कराने का प्रयास किया गया और लक्ष्य रखा पांच करोड़ अतिरिक्त रोजगार का। इस योजना में ऐसे रोजगार के प्रयास किये गये जो कि गुणवतापूर्ण हो।
- **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाः–** इस योजना का लक्ष्य तेजी से विकास का था लेकिन यह योजना पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी।
- **बारहवीं पंचवर्षीय योजनाः–** बारहवीं पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम योजना थी इसमें भी विकास का लक्ष्य रखा गया लेकिन यह लक्ष्य गैर कृषि

क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हुए विकास प्राप्ति का था।

मुख्य ग्रामीण विकास योजनाएंः–

- **स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजनाः–** इस योजना की शुरूआत 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्र को विकास की डगर पर ले आना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारम्भ पूर्ववर्ती योजनाओं जैसे दस लाख कुआं खुदाई योजना, टी0आर0वाई0एस0ई0एम0 आदि अनेक योजनाओं को मिलकर किया गया[iv]।
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–** यह योजना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई। इस योजना में अनेक छोटी–छोटी योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ दूर–दराज के गांवों में भी पहुंचा है क्योंकि विभिन्न माध्यमों(भामाशाह) से इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशनः–** यह योजना स्वरोजगार के पुनर्गठन के माध्यम से शुरू की गई। इसका लक्ष्य ग्रामों में रोजगार की उपलब्धता करवाने के साथ ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसमें ग्रामीण परिवारों की स्थिति के अनुसार सहयोग करना था।
- **ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रमः–** इस योजना की शुरूआत काम के बदले अनाज योजना का पुनर्गठन करके की गई। इसमें मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए विकास की डगर पर चलना था।
- **अंतोदया अन्न योजनाः–** इस योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना था जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम गेंहू जो कि निम्नतम मूल्य पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया। गेंहू के साथ चावल को इस योजना में शामिल किया गया था। यह भूखमरी और कुपोषण के विरूद्ध एक क्रांतिकारी प्रयास है।
- **प्रधानमंत्री जनधन योजनाः–** इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों और बैंकों के बीच व्याप्त दूरी को पाटना था। इस योजना के माध्यम से लोगों में धन संग्रह की प्रवृति और धन को बाजार में लगातार उपलब्ध करवाने का प्रयास था। साथ ही धन संग्रहण करने की प्रवृति से भविष्य में जरूरी कार्य में पैसे को लगाया जा सकता है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार योजनाः–** यह योजना उन ग्रामीणों के लिए थी जो कुछ स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके माध्यम से एक निश्चित स्तर(समय–समय पर बदलाव) तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उद्योग आदि हेतु सरकार ऋण साथ ही इसमें एक निश्चित अनुपात में सब्सिडी के रूप में सहायता ले सकता है।
- **सांसद ग्राम आदर्श योजनाः–** सांसद आदर्श योजना की शुरूआत महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए की गई। इस योजना की शुरूआत सन् 2014 में की गई और इसके पीछे मूल भावना ग्रामों के विकास की है। इस योजना के माध्यम से सांसद(राज्य सभा–लोक सभा) ग्रामों को गोद लेकर उनके विकास में तीव्रता लायेगा और 2019 तक इस हेतु 3–3 ग्रामों को प्रति सांसद लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें केवल 2019 तक का लक्ष्य ही नहीं रखा गया है इसको आगे बढाते हुए 2024 तक पांच अन्य ग्रामों का प्रत्येक सांसद के माध्यम से विकास किया जायेगा।
- **संसदीय क्षेत्र का विकासः–** सांसद द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया जायेगा और यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। जिसमें सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। 1992–93 में शुरू की गई योजना का लक्ष्य सांसद के संसदीय क्षेत्र विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास जैसे ग्रामीण क्षेत्र आदि के विकास से है।
- **इंदिरा आवास योजनाः–** यह योजना कुछ क्षेत्रों को अपवाद स्वरूप छोड़कर पूरे भारत में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को आवास उलब्ध करवाना है। क्योंकि रोटी और कपड़े के बाद आधारभूत सुविधाओं में मकान की आवश्यकता सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इस योजना से अनेक ग्रामीण परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया हो पाई है। समय–समय पर इसका नाम भी परिवर्तित किया जाता रहा है। यह योजना सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है, अगर इसमें व्याप्त कुछ स्तर के भ्रष्टाचार में सुधार किया जाये।
- **ए0पी0वाई योजनाः–** अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए लाभप्रद हो रही है जो कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगे हुए है। इस योजना के माध्यम से लोगो द्वारा संग्रहित राशि का उपयोग उनके वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में किया जायेगा। यह योजना उपर उल्लेखित प्रधानमंत्री जनधन योजना का ही एक भाग है।
- **मरू विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित कार्यक्रमः–** राजस्थान में इसकी शुरूआत काफी देर से 1995 में हुई। इसका संबंध कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास से था।
- **जीवन धारा योजनाः–** यह जवाहर रोजगार योजना से संबंधित है। इसके माध्यम से गरीब किसानों के उत्पादन में वृद्धि करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को विकास की और अग्रसर करना है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः–** 2015 में शुरू की गई योजना में बेहत्तर रोजगार देने हेतु लघु कालीन प्रशिक्षण देकर उसके पूर्व अध्ययन को मान्यता इसके माध्यम से दी जाती है। दिसम्बर 2017 तक इसके द्वारा 40 लाख[v] से भी अधिक लोगों को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- **एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रमः–** केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के माध्यम से बंजरभूमि को उपयोगी भूमि में बदलकर ग्रामीण जीवन स्तर की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करना है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामोंदय योजनाः–** प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए ग्रामों का तीव्रगति से उतरोत्तर विकास करना रहा है।
- **समंवित ग्रामीण विकास कार्यक्रमः–** इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए उनके जीवन स्तर को उच्चा उठाना और उनका जीवन सरस बनाना है।
- **भारत निर्माण कार्यक्रमः–** इस योजना में सड़क–पानी जैसी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध करवाना और ग्रामीण जीवन स्तर में बढोत्तरी करने से है।
- **उज्ज्वला योजनाः–** इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों हेतु गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है[vi], जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव और ग्रामीण लोगों को ज्यादा लाभ मिलना स्वाभाविक है।
- **बीस सूत्री कार्यक्रमः–** यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण गरीब श्रमिकों के हित में चलाया गया कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करते हुए ग्रामीण गरीब परिवारों के उत्पादन हेतु लोकहित के कार्यक्रमों का संचालन करना है। इसमें रोजगार की उपलब्धता, स्वच्छ जल, कृषि हेतु सुविधाएं जैसे सिंचाई आदि की व्यवस्था करना है।
- **मनरेगाः–** मरनेगा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि अब तक की जारी सभी योजनाओं में सबसे व्यापक है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरूआत 2006 में यू0पी0ए0 सरकार द्वारा की गई। मनरेगा के प्रत्येक परिवार को रोजगार का अधिकार दिया गया है। अगर यह रोजगार मांगे जाने पर सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो व्यक्ति या परिवार घर बैठे मुआवजे का हकदार होगा। इस प्रकार से यह कार्यक्रम कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे भारत में पिछलें 12 वर्षों से भी अधिक समय से भी जारी है। इस कार्यक्रम का प्रभाव इतना है कि यू0पी0ए0 सरकार के बाद बनी नई सरकार एन0डी0ए0 ने भी इसे आगे जारी रखा ही नहीं इसके बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।
- **अन्य योजनाएंः–** इन योजनाओं में वर्तमान एन0डी0ए0 सरकार द्वारा जारी की गई अपने शुरूआती समय की योजनाओं का भी अध्ययन किया गया है जो कि नये सीरे से शुरू की गई योजनाओं के अलावा वे योजनाएं भी है जिनका नाम बदल कर कुछ सुधार के साथ शुरू की गई। कुछ ऐसी भी योजनाओं का यहां वर्णन किया गया है जिनका सम्बंध केवल ग्रामीण विकास से नहीं है लेकिन इसमें गांवों की भागीदारी अधिक रही है। वर्तमान एन0डी0ए0 सरकार द्वारा वर्तमान में अनेक ग्रामीण हित की योजनाओं को शुरू किया गया है जो कि अभी अपनी शैशवावस्था में है।

उपरोक्त ग्रामीण कार्यक्रमों के अलावा भी अनेक छोटे–बड़े कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु आजादी के बाद से अनेक सरकारों द्वारा चालू किया गये। इन योजनाओं में कुछ योजनायें तो अधर में ही अटक गयी लेकिन अनेक ग्रामीण विकास संबंधित कार्यक्रम सफल भी रहे है, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत को पूरा करते हुए नजर आ रहे है। वर्तमान सरकार और आगे आने वाली सरकारों से ये उम्मीद की जा सकती है कि समय–समय पर ये अनेक योजनाओं को इसी प्रकार जारी रखेगें जिससे भारतीय कृषि प्रधान ग्रामीण परिवेश वाले राष्ट्र की उन्नति सम्भव हो सके। लेकिन ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल इनकी घोषणाएं और इनके एक बार चालू करना ही काफी नहीं है। इस हेतु इसका सफल संचालन करना भी अति आवश्यक है।

References

[i] शेरगील, बलदेव सिंह (जून–2019). रूरल इकॉनोमिक, स्टेट और पब्लिक पॉलिसी : इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्युम 54. इस्यु 26–27

[ii] चंद्र, प्रकाश (2017). ग्रामीण विकास एवं सशक्तिकरण में मनेगा की भूमिका : हनुमानगढ़ जिले का एक अनुभवात्मक अध्ययन. उदयपुर : एम.एल. एस.यू. पृष्ठ सं. 81.

[iii] कुमार, अनिल (2012). भारत में विकास और चुनौतियां. महेंद्र बुक कम्पनी : गुडगॉव. पृष्ठ सं. 160.

[iv] माखिजा, ए,एन (2013). ग्रामीण उद्यमिता विकास–अवसर एवं चुनौतियां, दिल्ली. अध्ययन पब्लिशर्स, पृष्ठ सं, 94.

[v] सृजा, ए (2018). ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार : कुरूक्षेत्र, जून. पेज न. 29.

[vi] आहुजा, राजीव (2018). सरकार का प्रयास : विकास बने जन आंदोलन : योजना, जून. पेज न. 14.

RRIJM 2015, All Rights Reserved